IF : 3.62 | IC Value 80.26

Volume-5, Issue-12, December - 2016 • ISSN No 2277 - 8160

Original Research Paper

Geography

^^ftyk Xokfy;j dh vFkZO;oLFkk dh leh{kk** HkkSxksfyd ifjizs{; esa

MkW fnO;k ikjk'kj — अतिथि शिक्षक (भूगोल/पर्यावरण अध्ययन) डॉ भगवत सहाय शा.महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

MkW 'kSysUnz flag rkSej — प्रोफेसर (भूगोल) शा. महाविद्यालय राघवगढ़ गुना (म.प्र.)

ABSTRACT

अपने सवृंत स्थित औद्योगिक क्षेत्रों की अर्थव्यस्था ग्वालियर जिले को एक अर्थतंत्र प्रदान करती हैं। परन्तु इन औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के अभाव में चलते कुछ औद्योगिक इकाइयाँ जीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। इस हेतु स्थानीय प्रशासन को रूबरू कराकर नई औद्योगिक नीतियों का निर्माण कर पुर्नउद्धार आवश्यक हैं ।

KEYWORDS :

वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकसित एवं विकासशील देशों के अर्यतंत्र के दायरें वर्ष दर वर्ष बदलते जा रहे हैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2016 की रिपोर्ट के आधार सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) के आधार विश्व के शीर्षस्थ दस देशों की सूची में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थानों पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिकार चीन जापान सूचीबद्ध हैं। वही सांतवे स्थान पर भारत को सूचीबद्ध किया गया हैं। अर्थव्यवस्था को आंकलित करने के प्रायः दो आधार होते हैं। प्रथम जी.डी.पी. एवं द्वितीय पी.पी.पी. (Purching Power Parity) जबकि पी.पी.पी. के आधार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के स्थानों चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत हैं। यह हमारे लिए अत्यन्त गौरवपूर्ण बात है, कि विश्व मानचित्र में 193 देशों की अर्थव्यवस्था में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। भारत एशिया महादीप का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ देश हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक विश्व का जी.डी.पी. में शीर्षस्थ अर्थव्यवस्था में तृतीय स्थान प्राप्त करना अनुमानित हैं। 1991 में भारत में तीव आर्थिक प्रगति हुई हैं यह उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों की नीतियों को लागू करने का परिणाम हैं। भारत का वर्तमान (2016) सकल घरेलू उत्पादन 7.6 प्रतिशत रहा। जो वर्ष 2017 तक 7.9 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होगा।

जिस प्रकार एक सुन्दर माला का सौन्दर्य उसमें पिरोये गयें मोतियों एवं मणियों से शोभायमान होता है, ठीक उसी प्रकार देश की उन्नति चाहे वाहे आर्थिक हो या सामाजिक उसके राज्यों, जिलो एवं नगरों के विकास से सम्भव हैं। भारत एक संघशासित देश हैं। इन संघ शासित देशों में मध्य प्रदेश राज्य को क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय स्थान प्राप्त हैं। जैसे कि, नाम से ही विदित हैं कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक विशाल राज्य हैं। जिसके अन्तर्गत 10 संभाग एवं 51 जिलें समाहित हैं। इन 10 जिलों में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जिला ग्वालियर स्थित हैं।

उपर्युक्त शोध पत्र ग्वालियर जिले की अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। यह जिला मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि समुचे भारत देश में अपने गौरवशाली इतिहास और विशिष्ट भू–आकृतिक लक्षणों के कारण प्रसिद्व हैं।

fLFkfr ,oa foLrkj %&

यह जिला ग्वालियर के राजस्व संभाग के अन्तर्गत हैं यह क्षेत्र मध्य भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसकी स्थिति पठारी हैं। यह जिला 25· 34′ और 26· 21′ उत्तरी अक्षांश तथा 77· 40′ और 78· 54′ पूर्वी देशान्तर तक विस्तारित हैं। यह मध्य प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.1 प्रतिशत हैं। 1956 में इस क्षेत्र को जिलें का स्वरूप मिला।

यह जिला उत्तर में मुरैना, पश्चिम में शिवुपरी, पूर्व में भिण्ड, तथा दक्षिण में दतिया जिले से गिरा हैं। इस जिले में तीन तहसील, चार विकासखण्ड़, तीन नगर पंचायत, दो नगर पालिका, तथा दो नगर पंचायत एवं एक नगर निगम स्थित हैं।

ftys dk {ks=Qy %&

rkfydk

जिला/ तहसील/ विकासखण्ड	औद्योगिक क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	आवाद ग्राम	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	मण्डल पंचायत
ग्वालियर	4565	566	298	04	01
गिर्द (तहसील)	2690	262	138	02	01
घाटीगॉव (विकासखण्ड)	1678	114	60	–	–
मुरार (विकासखण्ड)	857	148	78	01	–
पिछोर (तहसील)	975	150	79	01	–
डबरा (विकासखण्ड)	960	100	79	01	–
भितरवार (तहसील)	900	154	81	01	–
भितरवार (विकासखण्ड)	893	154	81	01	–

इस क्षेत्र की मुख्य विकसित औद्योगिक इकाइयॉ मालनपुर एवं बानमौर हैं जो कि क्रमशः भिण्ड एवं मुरैना जिले में स्थित है। इस औद्योगिक इकाइयों में लघु एवं बृहव आकार के औद्योग स्थापित हैं।

mn~ns'; %& उपर्युक्त शोध पत्र का उद्‌देश्य जिले के सवृंत औद्योगिक इकाइयों की स्थित एवं इनका प्रभाव ग्वालियर जिले की अर्थव्यवस्था पर दर्शाना, औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं की समीक्षा कर कारणों को ज्ञात करना एवं उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना हैं साथ ही ग्वालियर में नये औद्योगिक क्षेत्रों की सम्भावनाओं को दर्शाना हैं।

eq[; leL;k %&

1– ग्वालियर जिले की औद्योगिक विकास की सम्भावनाऐं उत्तम परिवहन जाल के अभाव में न हो पाना।

2– किसी महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज का उत्पादन न होने से उद्योग की स्थापना में बाधा होना।

3– उचित आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उद्योगपतियों एवं उद्योगों के निवेशकों को आकृषित न कर पाना।

fof/k ra= %&

इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से आंकड़ों का संकलन किया गया हैं। परन्तु मुख्यतः द्वितीयक आंकड़े अथवा प्रकाशित सामग्री के संकलन के शोध पत्र के समीक्षा की गई हैं। प्राथमिक आंकड़ों में मुख्य रूप से ग्वालियर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट, जिला सांख्यिकी पुस्तिका जबकि द्वितीय आंकड़ों में विश्व बैंक रिपोर्ट एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संचार माध्यमों से आंकड़ें प्राप्त किये गये।

leh{kk %&

ग्वालियर जिले में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डबलमेन्ट कॉर्पोरेशन (आई.आई.डी.सी.) के अनुसार ग्वालियर के सवृंत औद्योगिक क्षेत्र इस प्रकार हैं :–

1– मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र – पांच हजार एकड़

2– बानमौर औद्योगिक क्षेत्र – दौ सौ एकड़

इसके अतिरिक्त नवनिर्मित औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, स्टोर पार्क, रेडीमेड पार्क, आई.टी.पार्क, विकास होना शेष हैं

ग्वालियर जिले की जनसंख्या की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ग्वालियर से 32 कि.मी. दूर स्थित मालनपुर एवं 70 कि.मी. दूर बानमौर औद्योगिक इकाइयॉ हैं। इन औद्योगिक इकाइयों में लगभग आधा दर्जन से अधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियॉं उत्पादन कर रहीं हैं तथा 100 से अधिक इकाइयॉ बड़े स्तर पर कार्यरत् हैं। महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयॉ होने के बावजूद आधारभूत संरचनाओं को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। (सन् 2015 में हरियाणा की फ़ूड फेक्ट्री में यहॉं कि जलवायु और स्थिति को देखकर अपनी एक शाखा की स्थापना मालनपुर में की) इन उद्योगों के प्रथम और सबसे बड़ी बाधा यहॉं के परिवहन संजाल का विकसित न होना, जिसके कारण यहा का उत्पादित माल विपणन हेतु उचित स्थानों पर नहीं पहुंच पाता। द्वितीय बांधा इस क्षेत्र का पठारी होना है यह क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियों से उत्तम है क्योंकि यह न तो यह भूकम्प की कोई पेटी है न बाड़ का प्रकोप, न सुखे की सम्भावना न भू–स्खनन का भय। परन्तु खनिज की कोई मेखला की अवस्थिति न पाये जाने के कारण कोई भारी उद्योगों की स्थापना के लिए उत्तम दशायें नहीं हैं परन्तु इस बांधा का हल परिवहन के विकास से सम्भव हैं इस हेतु आईआईडीपी नें इस क्षेत्र के पुर्नउद्धार के लिए फोरलेन सड़कों के निर्माण का कार्य जारी किया हैं ताकि यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के सम्पर्क में आकर विकसित हो सके।

जल उद्योगों का आधार है। जिले की जीवन रेखा कहलाने वाली पार्वती एवं सिंध नदी रेत के उत्खनन उद्योग के लिए प्रसिद्व हैं। साथ ही इन नदियों पर बने अपर ककेटो, ककेटो और हरसी बांध जिले की जल आपूर्ति करते हैं। परन्तु इन क्षेत्र में अबैध रेत उत्खनन की समस्या ने विकट समस्या का रूप धारण कर लिया हैं। रेत के अवेध उत्खनन से आस–पास की भूमि पर खड्‌डों का निर्माण हो गया हैं। जिसके कारण जलीय पारिस्थितिकी के लिए खतरा बन गया है तथा कृषि भूमि पर मृदा के साथ मिश्रण से मृदा की उत्पादन क्षमता में निरतंर क्षीणता आती जा रहीं हैं।

उर्पयुक्त दोनों नदियों से करीब एक लाख हैक्टयर से अधिक क्षेत्र में सिचाई होती हैं। इस समस्या के निदान के लिए आवश्यक है, कि रेत का जो भी उत्खनन किया जाये वह स्थानिक प्रशासन के तत्वाधान में कानून एवं पर्यावरण संरक्षण के दायरें में हो। ताकि जिले की कृषि भूमि एवं पारिस्थतिकी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

ग्वालियर एक ऐसा स्थान है जो कि पूर्णतः भौगोलिक आपदाओं से मुक्त हैं इस क्षेत्र में सस्ती श्रम शक्ति, सुनियोजि प्रशासनिक व्यवस्था, सर्व सुलभ जलापूर्ति, विपणन हेतु बाजार उपलब्ध हैं। यह सभी कारक वे कारण है जो किसी औद्योगिक क्षेत्र को उन्नत बनाते हैं आवश्यकता है कि प्रशासन द्वारा परिवहन विकास के साथ ही औद्योगिक निवेशकों उचित विनियोग की सुविधा एवं राजस्व नीतियों में लचिलापन लाकर इस और आकर्षित करे ताकि यह क्षेत्र भी अन्य औद्योगिक विकसित क्षेत्रों की भाति पोषित हो सके।

InHk Iph %&
1 विश्व बैंक रिपोर्ट (आउटलुक, 2016)
2 जिला संख्याकी पुस्तिका, (ग्वालियर, 2016)
3 ग्वालियर विकास प्राधिकरण, (मास्टर प्लान, 2021)
4 जिला उद्योग कार्यालय, (रिपोर्ट, 2015)